बाद भी उत्तर प्रदेश ने उनके दल को वैसा समर्थन नहीं दिया जैसा वह चाह रहे होंगे। लेकिन वे देश के प्रधान मंत्री हैं और प्रधान मंत्री होने के नाते, देश के नेता होने के नाते लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना चाहिए। पिछला सत्र निकल गया। उत्तरांचल के लोग आशा भरी निगाहों से देखते रहे कि उनके लिए विधेयक आएगा, अलग राज्य का विधेयक आएगा। लेकिन वह विधेयक आया नहीं। सत्र बीत गया, और इस सत्र की जो सूची है उसमें शायद उत्तरांचल पर विधेयक की बात नहीं है, उत्तराखंड पर विधेयक की बात नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्रधान मंत्री जी ज्यादा लोगों का इम्तिहान न लें और इसी सत्र में ईमानदारी का पालन करते हुए राजनीतिक नैतिकता का पालन करते हुए, अगर उनको राज्य बनाना है, तो यह विधेयक प्रस्तुत करें और भा०ज०पा० की पूरी शक्ति उनको समर्थन करे और इसके आधार पर एक ऐसे अशांत क्षेत्र को जो देश की सुरक्षा में अग्रणी है, जो एक हजार वर्ष से देश की सुरक्षा में अग्रणी रहा है जहां का आदमी..**(समय की घंटी)** पूरी तरह से राष्ट्रीय भाव ने ओत प्रोत है ..**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): यह एक गंभीर मुद्दा है। आप कम से कम सरकार से कहिए कि इस मामले में—क्योंकि प्रधान मंत्री की घोषणा है 15 अगस्त को उत्तरांचल राज्य बनाने के बारे में—सरकार कुछ तो बताए कि इस सत्र में पास करेंगे कि नहीं।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: यह ठीक है कि प्रधान मंत्री जी वैसे एक दल के नेता नहीं हैं जैसे प्रधान मंत्री हुआ करते हैं। वे 15-16, 12-13 दलों की खिचड़ी सरकार के प्रधान मंत्री है। उनमें ऐसे भी लोग हैं जो किसी कारण से अपने प्रदेशों की समस्या के कारण—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—उसका विरोध कर रहे हैं लेकिन उन्हें याद करना चाहिए कि पी०सी० जोशी जैसे व्यक्ति ने जो उनके पूर्ववर्ती थे, उनके नेता थे, जब ये दल विभक्त नहीं हुए थे, बंटे नहीं थे, उसका समर्थन किया था-इस राज्य का, 1952 में। यह जो कांग्रेस पार्टी है, नेहरू जी ने 1937 में श्रीनगर की सभा में कहा था, जब देश आजाद नहीं हुआ था।

उपसभापति: दूसरे नाम लिखे हैं। जीरो आवर का समय खत्म हो गया है।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: चलिए।

उपसभापति: नहीं, आप कंक्लूड कर दीजिए। जो आपको मांगना है, प्रधान मंत्री जी से बोल दीजिए।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: तो नेहरू जी ने भी उसका समर्थन किया था। इस प्रकार से यह देश की एक ऐसी जायज मांग है जिसको न काश्मीर के साथ जोड़ा जा सकता है, न पंजाब के साथ जोड़ा जा सकता है, न मिजोरम के साथ जोड़ा जा सकता है, न नागालैंड के साथ जोड़ा जा सकता है और न गोरखालैंड के साथ जोड़ा जा सकता है। कोई प्रदेश अपने भाग के स्वयं विभाजन करने का संकल्प पारित नहीं करता लेकिन यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की दो दो सरकारों ने इसके विभाजन का प्रस्ताव पारित किया क्योंकि वहां के लोग पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं, पूरी तरह से देशभक्त हैं, देश की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में लगे हुए लोग हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इसी सत्र में उत्तरांचल का विधेयक प्रस्तुत करे और उसे पारित कराए।

डा० नौनिहाल सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं अपने को इससे एसोसिएट करता हूं।

RE: CHINESE PRESIDENT'S VISIT TO INDIA

डा० महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभापति महोदया।

मैं इस गरिमा सम्पन्न सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे देश में एक ऐसे मेहमान आए है जो एक प्रकार के इतिहास का निर्माण करने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति महामहिम जियांग झेमिन आज भारत की यात्रा पर आए हैं। हम सब भारत के लोग विश्व की इस प्राचीन संस्कृति के महान देश के नायक का यहां स्वागत करना चाहते है। हम इस बात को जानत है कि आज जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ईरान, भारत और चीन की मैत्री का विशेष महत्व है। जब आज विश्व सोवियत संघ के विघटन के बाद एक महाशक्ति के इर्दगिर्द घूम रहा है, वैसी विश्व व्यवस्था में चीन और भारत की मैत्री का विशेष महत्व है।

उपसभापति महोदया, अपने इस मेहमान का स्वागत करते हुए मैं इस बात को भूल नहीं सकता कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। महोदया, जब हम चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्त वह होता है जो मुंह के सामने खरी-खरी बात कहता है और पीठ के पीछे प्रशंसा करता है। जो मुंह के सामने प्रशंसा करते हैं वे

दोस्त नहीं होते, वे चाटुकार होते हैं। निश्चय ही हमारी दोस्ती चाटुकारिता नहीं होगी, हमारी दोस्ती दोस्ती होगी और इसलिए जब चीन पर साम्राज्यवादी अमरीका कोई आघात करना चाहेगा। तो भारत चीन के साथ खड़ा होगा, लेकिन जब चीन और भारत का आमना-सामना होगा तो चीन से हमें थोड़ी खरी-खरी बात करनी होगी। महोदया, अच्छा होता कि विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री जो हमारे सदन के सदस्य हैं वे भी अभी यहां होते। चीन के साथ वार्ता करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की संसद् ने शपथ ग्रहण की हुई है कि 1962 में चीन ने जो भूमि हथियाई थी उस एक-एक इंच भूमि को खाली करवाया जाएगा। 1962 के बाद इतना लंबा दौर गुजर गया वह भूमि अभी तक खाली नहीं हुई। हम इस तथ्य से गैर जानकार नहीं हैं महोदया, कि पाकिस्तान को शस्त्र देकर पाक अधिकृत काश्मीर के एक छोटे भू-भाग को चीन ने अपने कब्जे में किया हुआ है। यह तथ्य भी हमको मालूम है कि बर्मा को शस्त्र सप्लायी करके अंडेमान-निकोबार के पास एक छोटे द्वीप पर भी चीन ने अपना कब्जा जमा लिया है। उत्तर में हिमालय में और दक्षिण में हिन्द महा सागर, वहां पर चीन के सैनिक अड्डे स्थापित हुए है। महोदया, हिन्द सागर में..... (व्यवधान)

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa) : Madam, is he welcoming the President of China? We are going to enter ..... *(Interruptions)* ....into a bilateral agreement. *(Interruptions)* Our foreign policy has changed. *(Interruptions)*.

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, he should not ....*(Interruptions)*.

SHRI JOHN F. FERNANDES: On the one hand he is digging all the past events and on the other hand he is welcoming the President of China. It will not solve the problem. We should welcome our guest. *(Interruptions)*. Let us have a debate. Then we will also speak on that. *(Interruptions)*. There are irritants. We know that. But we are not going to bring in those irritants now. It will affect our friendly relationship with this country. Madam, I request you not to permit all this. *(Interruptions)*.

डा० महेश चन्द्र शर्मा: उपसभापति महोदया, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं ..... (व्यवधान)

उपसभापति: आप जरा एक मिनट बैठिए। ..... (व्यवधान)

SHRI JOHN. F. FERNANDES: He has been permitted to welcome the President.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. Mr. Sharma, the hon. Chairman has permitted you to welcome the hon. President of China on the occasion of his visit to India. The hon. Chairman has permitted you to welcome him. he was under the impression that you would welcome him.

आपके घर कोई महमान आता है तो आप यह थोड़े ही कहते हैं कि हमारा-तुम्हारा पुराना कभी झगड़ा हुआ होगा। वह कोई आ रहा है तो उसका आगमन करते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं। आगर पहले ही से इस तरह की बात करेंगे तो आईंदा के लिए आप कोई अच्छा रास्ता थोड़े ही खोल रहे हैं। आप सामने तलवार रख कर किसी को सोने का निवाला देंगे तो वह कैसे खायेगा? ....(व्यवधान) दिस इज़ नाट द वे। यह हमारे देश की न परंपरा है, न सभ्यता है। हमारे देश की परंपरा और सभ्यता तो यह कि हमारे देश का मेहमान भगवान के बराबर होता है। .... (व्यवधान)

डा० महेश चन्द्र शर्मा: महोदया, मेरी बात पूरी सुन तो लें।

उपसभापति: आप क्या कह रहे हैं? .... (व्यवधान)

डा० महेश चन्द्र शर्मा: मेरी बात पूरी सुनी गई होती। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है।

उपसभापति: आपकी बात जो आपका टॉपिक है उसके बिल्कुल विरुद्ध जा रही है, इसलिए मैं परमिट नहीं करूंगी। क्योंकि यह एक .... (व्यवधान)

डा० महेश चन्द्र शर्मा: महोदया, मैं चीन के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहा हूं। ..... (व्यवधान)

उपसभापति: यह स्वागत आप गलत कर रहे हैं। .... (व्यवधान)

डा० महेश चन्द्र शर्मा: और अपनी भावनाओं का इजहार उनके सामने कर रहा हूं। ....(व्यवधान)

उपसभापति: आप उनको मिल कर कर दीजिए ....(व्यवधान) यहां हाउस में मत करिए।..... (व्यवधान)

डा० महेश चन्द्र शर्मा: अपने मेहमान के सामने .... **(व्यवधान)** महोदया, मैंने कोई आरोप तो नहीं लगाया .... **(व्यवधान)**

उपसभापति: नहीं-नहीं .... **(व्यवधान)**

डा० महेश चन्द्र शर्मा: आप देखिए मैंने उन पर एक भी आरोप अगर लगाया हो तो मैं अपना आरोप वापस लूंगा। .... **(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): वाजपेयी भी यह इंडोर्स नहीं करते जो आप बोल रहे हैं। .... **(व्यवधान)**

डा० महेश चन्द्र शर्मा: मुझे नहीं मालूम कि आप इस बात को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, पर मुझे यह मालूम है कि हिन्दुस्तान का आम आदमी इस बात को जानता है और समझता है कि .... **(व्यवधान)** .... मेहमान को पहुंचायी जानी चाहिए।

मैं चीन के राष्ट्रपति का भारत की भूमि पर स्वागत करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Zero Hours is over.

SPECIAL MENTIONS

Power Grid in Multi-crore Scam Corporation of India

SHRI PARAG CHALIHA (Assam): Madam, Deputy Chairperson, through you I would like to draw the attention of the House to yet another scam. As reported in the *Hindustan Times,* dated the 18th and the 20th November, 1996 massive irregularities have been perpetrated by Officials of the State-owned Power Grid Corporation of India in the purchase of power transmission related equipment worth crores of repees.

These irregularities relate to purchase of emergency restroration systems in which astronomical sums totalling to Rs. 32.58 crores have been paid to a U.S. firm, namely, Lindsey, through a string of vendors. The equipment normally costs not more than Rs. 6.6 crores.

What is surprising is the fact that neither the Ministry of Power nor the Central Electricity Authority had approved the import of the equipment though they were under obligation to do so.

What is even more surprising is that the E.R.S. (Emergency Restoration System) is neither techno-economically viable nor will it be of any use for teackling the problem of failed transmission in Indian conditions.

What is alarming is the fact that the equipment was purchased on the suggestion of the World Bank. No separate open tender was floated by the Power-Grid Corporation of India for this purpose. On the contrary, it was procured quietly, in a clandestine manner as a part of the lumpsum contract for executing transmission tower-cum-transmission network to evacuate power from Vindhyachal and Naptha- Jhakri powr projects of the NTPC and the NJPC.

It is alarming to note that no separate approval had been sought from the Power Grid's Board of Directors for the import of the said equipment.

In both the quotations which were given by the controversial firm, Lindsey, they had offered to supply the said E.R.S. equipment at a price of Rs. 8,54,237 per set.

The principles of commercial jurisprudence demand that the negotiated price should be lower than the price quoted in the initial offer.

But surprisingly, Power Grid procured the equipment through the vendors at a much higher price. The higher price paid only indicates the fraudulent nature of the import transaction perpetrated by the Power Grid. Now the files have been reportedly removed from the office. We urge upon the minister for Power to make an immediate statement on the issue and also to initiate an inquiry into the matter.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR (Assam): I would like to associate myself with the hon. Member on this